खेलों की दुनिया में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करते हुये वर्ल्ड आर्चरी (तीरंदाजी) चैम्पियनशिप-2023 में भारतीय टीम ने दो गोल्ड मैडल जीते हैं। भारतीय पुरुष और महिलाओं की कम्पाउण्ड आर्चरी टीम ने पैरिस में शनिवार को गोल्ड मैडल जीता। भारत ने दो स्वर्ण और तीन कांस्य पदक समेत पांच पदकों के साथ अपने विश्व कप अभियान का समापन किया। भारत की पुरुष कम्पाउण्ड आर्चरी टीम, जिसमें ओजस प्रवीण देवताले, प्रथमेश जावकर और अभिषेक वर्मा शामिल थे, ने फाइनल मुकाबले में यू.एस.ए. को 236-232 से हराकर वर्ल्ड चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं पैरिस में 15 से 20 अगस्त तक जारी इस प्रतियोगिता में, चित्र में नज़र आ रही, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद और स्वामी परनीत कौर की महिला कम्पाउण्ड आर्चरी टीम ने गोल्ड मैडल जीता और यह भारत का इस विश्व कप में पहला गोल्ड मैडल है। टीम ने बेहद करीबी मुकाबले में मैक्सिको की टीम को चार राउंड तक चले मैच में 234-233 से हराकर पोडियम के शीर्ष पर जगह बनाई। गौरतलब है कि, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर की तिकड़ी ने मिलकर इस महीने की शुरुआत में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत की पहली महिला कम्पाउण्ड टीम का गोल्ड मैडल जीता था।

माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाला, 53 प्रतिशत अभ्यर्थी फर्जी मिले

स्कूल-कॉलेजों ने गत 5 वर्षों में केन्द्र सरकार को 144.83 करोड़ रु. से अधिक का चूना लगाया

- **जांच के शुरुआती चरण में 1572 संस्थानों में से 830 को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। मंत्रालय का स्कॉलरशिप कार्यक्रम लगभग एक लाख 80 हजार संस्थानों तक फैला हुआ है। इस लिहाज से यह अरबों-खरबों रुपयों से अधिक का घोटाला हो सकता है।**
- **केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री स्मृति ईरानी ने मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपने का आदेश दिया।**

नई दिल्ली, 19 अगस्त। भारत के सबसे बड़े माइनॉरिटी स्कॉलरशिप (अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति) घोटाले का पता चला है। देश में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लगभग 53 प्रतिशत लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई एक आंतरिक जांच में 830 संस्थानों में गहरे भ्रष्टाचार का पता चला है। इसके जरिए पिछले 5 वर्षों में 144.83 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के पास भेज दिया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 10 जुलाई को इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान 34 राज्यों के 100 जिलों में पूछताछ की गई। जांच किए गए 1572 संस्थानों में से 830 को धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। यहां दिलचस्प बात ये है कि ताजा आंकड़े 34 में से केवल 21 राज्यों के हैं। यानी बचे हुए 13 राज्यों के संस्थानों की जांच अभी भी चल रही है। फिलहाल, अधिकारियों ने इन 830 संस्थानों से जुड़े खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। मंत्रालय का छात्रवृत्ति कार्यक्रम लगभग 1,80,000 संस्थानों तक फैला हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्र शामिल हैं। यह पहल शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 में शुरू की गई थी। कार्यक्रम के लिए फर्जी लाभार्थियों के जरिए इन संस्थानों द्वारा हर साल अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का दावा किया गया था।

सी.बी.आई. इन संस्थानों के उन नोडल अधिकारियों की जांच करेगी जिन्होंने अप्रूवल रिपोर्ट दी। इसके अलावा, जिला नोडल अधिकारी भी जांच के घेरे में आएंगे जिन्होंने फर्जी मामलों का सत्यापन किया और कैसे कई राज्यों ने इस घोटाले को वर्षों तक जारी रहने दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने यह भी सवाल उठाया है कि बैंकों ने फर्जी आधार कार्ड और के.वाई.सी. दस्तावेजों के साथ लाभार्थियों के लिए फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में जांच के दौरान सभी 62 संस्थान फर्जी या निष्क्रिय पाए गए। राजस्थान में जांच किए गए 128 संस्थानों में से 99 फर्जी या गैर-परिचालन थे। असम में चौंकाने वाली बात यह है कि 68 प्रतिशत संस्थान फर्जी पाए गए। कर्नाटक में 64 फीसदी संस्थान फर्जी पाए गए। उत्तर प्रदेश में 44 फीसदी संस्थान फर्जी पाए गए। केरल के मलप्पुरम में, एक बैंक शाखा ने 66,000 छात्रवृत्तियां वितरित कीं, जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र अल्पसंख्यक छात्रों की पंजीकृत संख्या से अधिक है।

तेलंगाना में क्या...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थानापन्न तलाशना जरूरी है क्योंकि वे अपने चुनाव क्षेत्रों में घोर सत्ता-विरोध का सामना कर रहे हैं। अगर इन विधायकों को टिकट नहीं दिये जाते तो पार्टी असंतुष्टों और बागियों को सँभाल सकती है। इसके अतिरिक्त बगावत की स्थिति में, पार्टी माइक्रो-मैनेज की योजना की भी तैयारी कर रही है।

बी.आर.एस. जहाँ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बारे मे सोच रही है, वहीं वह इस संभावना से भयभीत भी है कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिये जायेंगे, वे या तो किसी दूसरी पार्टी में चले जायेंगे या फिर बागी उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा गया है कि वे संभावित बागियों से बातचीत करके, उन्हें किसी भी तरह सँभालें। चन्द विधायक ऐसे भी हैं, जिन्हें यह आशंका है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जायेगा, इसलिये उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को हराने के लिये काम करने की धमकी देना शुरु कर दिया है।

इस बीच, भाजपा ने दूसरे राज्यों के विजेता विधायकों की सेवाएँ लेना भी शुरु कर दिया है ताकि पार्टी प्रत्याशियों का मार्ग दर्शन कर सके। 119 भाजपा प्रत्याशियों में से प्रत्येक प्रत्याशी को एक "शैडो" प्रत्याशी मिलेगा, जो विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपनी जानकारियाँ प्रदान करेगा।

तेलंगाना लाए जाने वाले विधायकों की पहली खेप में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी तथा तमिलनाडु के विधायक शामिल हैं। वे प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक सप्ताह का समय देंगे।

इस बीच, कांग्रेस ने प्रत्याशी-चयन के तौर-तरीके शुरु कर दिये है तथा उम्मीदवारी के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की प्रक्रिया घोषित कर दी है। पार्टी मुख्यालय पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में किये जाने वाले आवेदनों के साथ, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का 50,000 रू. तथा एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों को 25,000 रू. जमा करने होंगे।

संभावित उम्मीदवारों के आँकलन के लिये उनसे यह अपेक्षा की गई ह कि वे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दें। दरअसल, ऐसा माना जा रहा है कि प्रचार में, तथा कुल मिलाकर पूरे चुनाव में ही, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी एवं महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को यह वचन देना होगा कि वे पार्टी के लिए काम करते रहेंगे।

कांग्रेस पार्टी अपने पूरे प्रचार तथा चुनाव लड़ने की रणनीतियों में, कर्नाटक विजय से मिली कुछ सीखों एवं सबकों को भी काम में ले रही है।

राहुल अपनी बाइक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्विटर पर शेयर की और लिखा "ऊपर और आगे-अविरल।" के.टी.एम. 390 एडवेंचर एक 373 सी.सी. की बाइक है जिसमें 43 बी.एच.पी. की अधिकतम पावर 37 एम.एम. का उच्चतम टो:क इस बाइक की सर्वाधिक स्पीड करीब 170 कि.मी. प्रति घंटा है। राहुल गांधी पहले बता चुके थे कि उनके पास एक "के.टी.एम. 390" बाइक है लेकिन उनका सिक्योरिटी कवर उन्हें इसे चलाने की अनुमति नहीं देता है। गांधी ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह दिल्ली के करोल बाग मार्केट के आला दर्जे के मैकेनिकों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इसमें उन्हें बाइक सर्विस से संबंधित जानकारी जुटाते हुए देखा गया।

राहुल गांधी ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में उन्होंने यह बात साझा की कि उनके पास एक के.टी.एम. बाइक है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा-"मेरे पास एक के.टी.एम. 390 बाइक है, लेकिन यह अब तक इस्तेमाल नहीं हुई है, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी के लोग मुझे इसे चलाने नहीं देते।" इस माह की शुरूआत में राहुल गांधी को तमिलनाडु के ऊटी के निकट मुथुनाडु गांव में टोडा आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ डांस करते हुए देखा गया था। न्यूज एजेंसी ए.एन.आई. द्वारा ट्विटर पर शेयर एक क्लिप में राहुल गांधी को परम्परागत शॉल पहने हुए स्थानीय निवासियों के साथ घेरा बनाकर डांस करते हुए दिखाया गया।

टमाटर और दालों के बाद अब प्याज भी महंगी होने की आशंका

केन्द्र सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुये प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत एक्साइज़ ड्यूटी लगाने की घोषणा की

नई दिल्ली, 19 अगस्त (वार्ता)। सरकार ने देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर उसकी कीमत शांत रखने के लिए रसोई में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली इस वस्तु के निर्यात पर 40 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने की शनिवार को घोषणा की।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 40 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगा दिया है जो 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने की अधिसूचना राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है।

प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने के बनने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय जनहित के लिए आवश्यक था। गौरतलब है कि खाद्य वस्तुएं और तमाम मौसमी फल-सब्जियों तथा कुछ अन्य वस्तुओं की खुदरा कीमतों में तेजी के चलते जुलाई में खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति उछलकर 7.44 फीसदी पर पहुंच गई।

जून,2023 माह में खुदरा मुद्रा स्थिति 4.87 प्रतिशत थी। जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति 11.5 फीसदी थी। सितंबर 2022 के बाद पहली बार खुदरा मुद्रास्फीति सात सबसे ऊपर गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्याज का खुदरा भाव इस वर्ष जून के मुकाबले जुलाई में खुदरा कीमत 28 प्रतिशत चढ़ गया था। जुलाई, 2022 की तुलना में इस बार जुलाई में प्याज की खुदरा कीमतें औसतन 7.13 फीसदी ऊपर चल रही थीं।

सरकार का अनुमान है कि 2022-23 फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन तीन करोड़ दस लाख टन के आस पास होगा।

एक और सिंधिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विचारधारा, प्रथाओं, सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था तथा पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा के चलते बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुये हैं। उनकी सच्चाई उन्हें यहाँ लेकर आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को इस सच्चाई से अवगत करायेंगे।"

नाथ ने कहा कि चौहान सरकार न केवल भ्रष्टाचार में बल्कि महिलाओं, किसानों एवं युवाओं के उत्पीड़न के मामले में नम्बर एक है। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता ने शिवराज सरकार को अलविदा कहने का पक्का निश्चय कर लिया है। उन्होंने कहा, "मैं भी उन्हें अलविदा कहूँगा, लेकिन प्यार के साथ।" इस बीच, पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वापस आकर वे बहुत खुश हैं। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर नहीं है, जब सिंधिया के प्रति निष्ठा रखने वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है।

अभी हाल ही में, शिवपुरी के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बैजनाथ सिंह यादव, जो सिंधिया के साथ जिले के कोलारस क्षेत्र में काम कर रहे थे, अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये थे। सिंधिया के एक और सहयोगी राकेश गुप्ता, जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुये हैं, ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी तथा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में लौट आए।

प्रिविलेज पैनल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की औपचारिक सुनवाई करने के बाद, उनके निलंबन को रद्द करने के पक्ष में प्रतीत हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान उनके "उच्छृंखल आचरण" को लेकर, स्पीकर ओम बिड़ला ने चौधरी सदन की सदस्यता से, प्रीविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक के लिये, निलंबित कर दिया था। शुक्रवार को हुई कमेटी की मीटिंग में कई सदस्यों ने ऐसा महसूस किया कि स्पीकर ने चौधरी को उनके आचरण के लिये सजा दे दी है तथा उनके व्यवहार की और जाँच-परख की जरूरत नहीं है।

कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि "किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने भी इस मुद्दे पर नरम रूख अपनाया और वे उने निलंबन को वापस लेने के पक्ष में थे। कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि "नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया के तहत कमेटी ने 30 अगस्त की मीटिंग में चौधरी का पक्ष सुनने का निर्णय लिया है।

'आगामी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डोटासरा ने बताया कि 21 से लेकर 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में बैठक की जाएगी। जो भी आवेदन आएंगे, उन्हें इन कमेटियों में 24 तारीख को बैठक में पेश किया जाएगा और 25 अगस्त से प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर जिलों में जाकर टिकट के दावेदारों पर फीडबैक लेंगे। फिर कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा पांच दावेदारों का पैनल बनाया जाएगा। इसके बाद 27 से 31 अगस्त तक

- **मुख्यमंत्री के बयानों से ऐसा भी लगता है कि, वर्तमान विधायकों में से अधिकांश को दोबारा टिकट मिल सकता है।**

स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई राजस्थान में रहेंगे और संभाग स्तर या जिला स्तर पर जाकर नेताओं वे कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम तय करेंगे।

सभी दावेदारों को एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, जिसे भरकर जमा कराना होगा। बैठक में सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोंदियाल, अभिषेक दत्त, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन और काज़ी निज़ामुद्दीन सहित प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह और राजेंद्र यादव के अलावा सभी सदस्य मौजूद थे।

बलात्कार पीड़िता की गर्भपात याचिका 12 दिनों तक टालने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ

गुजरात हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह लापरवाही नहीं बहुत बड़ा अन्याय है

नई दिल्ली, 19 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भपात कराने की उसकी याचिका को 12 दिनों तक टालने पर गुजरात उच्च न्यायालय की शनिवार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, बल्कि तत्परतापूर्वक निपटा जाना चाहिए।

गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई टालने का आदेश 17 अगस्त को पारित किया गया था। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बैंच ने गुजरात के एक मामले में विशेष सुनवाई करते हुए भ्रूण को हटाने की संभावना का पता लगाने के लिए भरूच की एक मैडिकल बोर्ड से एक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

बैंच ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई कर इस मसले पर विचार करेगी। पीड़िता के अधिवक्ता ने बैंच के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की तारीख 23 अगस्त तय की है, जिससे उसकी गर्भावस्था 28 सप्ताह की हो जाएगी।

अधिवक्ता ने हालांकि कहा कि, याचिका सात अगस्त को दायर कई और 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी। उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष यह भी कहा कि याचिकाकर्ता महिला को चार अगस्त को अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला और उसने सात अगस्त को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत की बैंच के समक्ष यह भी कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय का आदेश रिकॉर्ड पर भी उपलब्ध नहीं था।

शीर्ष अदालत की बैंच ने उच्च न्यायालय का आदेश उपलब्ध नहीं होने की याचिकाकर्ता के वकील की बात पर कहा, अगर विवादित आदेश मौजूद ही नहीं है तो हम कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। इस मामले को स्थगित करने में मूल्यवान दिन बर्बाद हो गए हैं। देखिए, ऐसे मामलों में तात्कालिकता की भावना होनी चाहिए न कि उदासीन रवैया। हमें ऐसी टिप्पणियाँ करने के लिए खेद है। हम इसे सोमवार को पहले मामले के रूप में सूचीबद्ध करेंगे।

शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि चूंकि कीमती समय पहले ही बर्बाद हो चुका है, इसलिए भरूच के मैडिकल बोर्ड से नई रिपोर्ट मांगी जा सकती है।

अमूल भारत का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ स्थापित जी.सी.एम.एम.एफ. के पास आज गुजरात के भीतर 18 सदस्य संघ हैं जो प्रतिदिन तीन करोड़ लीटर से अधिक दूध एकत्रित करते हैं और 72,000 करोड़ रुपये (नौ बिलियन यू.एस. डॉलर) के समूह कारोबार के साथ अमूल भारत का सबसे बड़ा एफ.एम.सी.जी. ब्रांड बन गया है।

जी.सी.एम.एम.एफ. की 49वीं वार्षिक आम सभा 19 अगस्त को आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान जी.सी.एम.एम.एफ. के अध्यक्ष शामलभाई पटेल ने बताया कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इस सहकारी संगठन ने वर्ष 2022-23 में कारोबार में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। वर्तमान में अमूल दुनिया का 8वां सबसे बड़ा डेयरी संगठन है और इसने वर्ष 2022-23 में 11,000 करोड़ का अतिरिक्त समूह कारोबार जोड़ा है। इसके साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा एफ.एम.सी.जी. ब्रांड बन गया है।

पटेल ने कहा कि बीते 50 वर्षों में हम डेयरी किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु बनने के सिद्धांत पर खरा उतरने में सफल रहे हैं। जिस विज़न के साथ हमारे छह संस्थापकों - त्रिभुवनदास पटेल, मोतीभाई चौधरी, गलबाभाई पटेल, भूराभाई पटेल, जगजीवनदास पटेल, जशवंतलाल शाह और डॉ. वर्गीस कुरियन द्वारा जी.सी.एम.एम.एफ. की स्थापना की गई थी, उसने अमूल को पीढ़ियों से प्रत्येक भारतीय का सबसे अधिक पसंदीदा ब्रांड बनाया है।

उन्होंने डेयरी विकास के अमूल मॉडल ने डेयरी किसान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर मॉडल बनाकर भारत को दुनियाभर में गौरवान्वित किया है। आज, हम गर्व से कह सकते हैं कि, गुजरात के डेयरी किसानों ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसके बारे में बहुत कम लोग सपना देख सकते हैं। एक ऐसा ब्रांड जिसका स्वामित्व वास्तव में 36 लाख डेयरी किसानों के पास है। अपनी मजबूत और चुस्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ हमारा लक्ष्य दुनियाभर में ग्राहकों तक पहुंचना है।

चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैण्डिंग के बाद सूर्य मिशन लॉन्च करने में जुट जायेगा इसरो

अब इसरो की नज़र सौरमंडल के सबसे गर्म और सबसे बड़े सदस्य सूर्य की सबसे चुनौतीपूर्ण सतह पर उतरने पर है

- **इसरो के अनुसार, आदित्य -एल-1 अंतरिक्ष मिशन भेजने का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य कोरोनल हीटिंग और सौर पवन वेग को समझना है। इससे रिअल टाइम (एक निर्धारित समय) में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी।**
- **इसरो सूर्य की यू.वी. स्पैक्ट्रम की विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर यह जानने का प्रयास करेगा कि, आखिर किन प्रत्यक्ष कारणों से हवा की दिशा बदलती है।**

चेन्नई, 19 अगस्त (वार्ता)। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) की नजर चंद्रमा के बाद अब सौरमंडल के सबसे गर्म और सबसे बड़े सदस्य सूर्य की सबसे चुनौतीपूर्ण सतह की पर उतरने पर है।

अंतरिक्ष एजेंसी सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य-एल 1 सौर अन्वेषण मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी कर रही है। आदित्य-एल 1 मिशन को इसरो पी.एस.एल.वी. रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एस.एच.ए.आर. (एस.डी.एस.सी.-एस.एच.ए.आर.), श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जायेगा।

इसके बाद कक्षा को और अधिक अण्डाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑन-बोर्ड प्रणोदन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु एल-1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा।

एल-1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए सैटलाइट को बिना किसी ग्रहण/ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा।

जैसे ही अंतरिक्ष यान एल-1 की ओर यात्रा करेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र (एस.ओ.आई.) से बाहर निकल जाएगा। एस.ओ.आई. से बाहर निकलने के बाद, क्रूज़ चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को एल 1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लॉन्च किये जाने के बाद से एल 1 तक की कुल यात्रा में आदित्य-एल 1 को लगभग चार महीने लगेंगे।

इसरो के अनुसार, आदित्य -एल 1 अंतरिक्ष मिशन भेजने का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों में कोरोनल हीटिंग और सौर पवन वेग को समझना है। इसरो ने कहा कि, आदित्य -एल 1 अंतरिक्ष यान को पोलर सैटेलाइट लांच व्हिकल (पी.एस.एल.वी.) के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा (एल.इ.ओ.) प्रक्षेपित किया जायेगा।

अन्य उद्देश्यों में कोरोनल मास इजेक्शन (सी.एम.ई.), फ्लेयर्स और निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत को समझना शामिल है। यह सौर वातावरण में सौर पवन वितरण और तापमान अनिसोट्रॉपी के साथ-साथ युग्मन और गतिशीलता को भी समझता है।

इसरो ने सूर्य मिशन की विशिष्टता पर कहा कि यह पहली बार निकट यूवी बैंड में स्थानिक रूप से विघटित सौर डिस्क का अध्ययन करेगा जो सी.एम.ई. गतिशीलता सौर डिस्क के करीब होगी जिससे सी.एम.ई. के त्वरण शासन में जानकारी प्रदान की जाएगी जो लगातार नहीं देखी जाती है।

अनुकूलित अवलोकनों और डेटा वॉल्यूम के लिए सी.एम.ई. और सौर फ्लेयर्स का पता लगाने के लिए यान में ऑन-बोर्ड इंटेलिजेंस, बहु-दिशा अवलोकनों का उपयोग करके सौर हवा की दिशात्मक और ऊर्जा अनिसोट्रॉपी जैसी अनूठी विशेषताएं शामिल हैं।

जैनरिक दवा मामले में डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख हुआ

- **सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व सभी राज्य सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा।**

नई दिल्ली, 19 अगस्त। जैनरिक दवाओं के चलन को बढ़ावा देने के लिए पहले डॉक्टरों को निर्देश दिया गया था कि वह मरीजों को जैनरिक दवाएं ही लिखे। मगर यह प्रेक्टिस पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है और डॉक्टर्स अभी भी अपने मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ मुहैया कराई जाने वाली दवाओं को ही लिख रहे हैं। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें दखल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जैनरिक दवाएं नहीं लिखने वाले सभी डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) से जवाब मांगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने एक वकील किशन चंद जैन की तरफ से दायर याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें शिकायत की गई थी कि भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के बावजूद, स्पष्ट रूप से डॉक्टरों को केवल जैनरिक दवाएं लिखना अनिवार्य है।

डॉक्टर केवल महंगी ब्रांडेड दवाओं को ही बढ़ावा देते रहते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जैनरिक दवाओं (ऑफ-पेटेंट) की कीमतें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। कीमत में यह अंतर जैनरिक दवाओं को आबादी के व्यापक वर्ग के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाता है।

दवाओं की सामर्थ्य और पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में दवाओं में जैनरिक नामों का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियम लागू किए हैं। वकील ई.सी. अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में 2002 के नियमों का हवाला दिया गया, जिसमें डॉक्टरों को केवल उनके जैनरिक नाम से दवाएं लिखने का आदेश दिया गया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908